

न्यायालय अपरजिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 04 / 2016

अपीलार्थी—

भंवरलाल पुत्र मूलाराम जाति  
ब्राम्हण निवासी बायतु तहसील  
बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता—

राजस्थान राज्य जरिये  
तहसीलदार बायतु

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 04.02.2016 जो प्रकरण सं. 02/2016 सरकार बनाम भंवरलालमे तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-


1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16 / 02 / 2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बायतु द्वारा प्रकरण सं. 02/2016 सरकार बनाम भंवरलाल मे पारित निर्णय दिनांक 04.02.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का बायतु चिमनजीद्वारा तहसीलदार बायतु के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्रामबायतु चिमनजी के खसरा नम्बर 965/529 रकबा 03-02 बीघा किस्म बा०दो० में से 1000 वर्गफीट भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ ईंटों बनाने का कारखाना स्थापित कर खातेदारी भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बायतु द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 90(ए) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के




  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ किन्तु नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी मानते जुर्माना रूपये 15000 आरोपित किया जाकर विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 01.03.2016 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना एवं बेदखलीका अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।
5. अपीलांट्सकी ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की तलबी हेतु जारी नोटिस स्वयं अपीलांट पर तामील नहीं होकर अपीलांट के घर पर रूबरू मौतबिरान के चरपा किया गया है जबकि मौतबिरान का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। अपीलाधीन कार्यवाही में जारी नोटिस में अपीलांट का 5000 वर्गफीट पर अनाधिकृत कब्जा अंकित किया गया है जबकि हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में 10000 वर्गफीट भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार नोटिस में प्रकरण सं.



  
अपर कलक्टर राड़मुर  
(ए.डी.एम.)

2/2016 अंकित हैं जबकि निर्णय में प्रकरण सं. 01/15 अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि के लिये अपीलांट के विरुद्ध अपीलाधीन कार्यवाही की गई है वह खसरा नम्बर 965/529 रकबा 03-02 बीघा भूमि चार खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें से अपीलांट का 1/12 हिस्सा आता है जिस पर अपीलांट ने अपना हिस्सा सुरक्षित करने हेतु ईटों की दीवार के लिये ईटे डलवाई थी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा द्वेषभावना पूर्वक अपीलांट को हानि पहुंचाने की गरज से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज करवाया गया है। अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर ईटों की दीवार बनाना कोई गलत कार्य नहीं है तथा न ही अपीलकर्ता ने उक्त भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही दर्ज कर लिया एवं इस बाबत मुर्तिब की गई मौका रिपोर्ट अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय तैयार की गई है। इस प्रकार बिना अपीलांट की सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत/मौका रिपोर्ट रेकॉर्ड पर लिये, अपीलांट को कथित रूप से अतिक्रमी मानना कतई न्यायोचित नहीं होगा। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु के द्वारा प्रकरण सं. 02/2016 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2016 अपास्त किये जाने का आदेश पारित करावें।

6. रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम बायतु चिमनजी के खसरा नम्बर 965/529 रकबा 03-02 किस्म बा0दो0 खातेदारी भूमि में से 10000 वर्गफीट भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ ईटों का कारखाना स्थापित कर अनाधिकृत रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है, इस पर अपीलांट को नोटिस जारी किया किन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस एवं सतुष्टिपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर अपीलांट के विरुद्ध धारा 90(ए)(5) के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलांट को मुतनाजा भूमि पर



अवैध अतिक्रमी घोषित किया गया है एवं अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित कर बेदखली का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटने अपनी संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 965/529 रकबा 03-02 बीघा में अपने 1/12 हिस्से पर काबिज होना प्रकट किया है, किन्तु हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार 10000 वर्गफीट भूमि पर ईंटे बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। इस आशय की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा अपीलांट के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर की गई है। ग्रामवासियों द्वारा शिकायत में उल्लेख किया है कि अपीलांट के खातेदारी खेत से होकर पुराना कदीमी रास्ता गुजरता है जिसे अवरुद्ध करने के उद्देश्य से अपीलांट द्वारा इस पर ईंटों का प्लांट स्थापित कर दिया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का अनाधिकृत रूप से गैर कृषि उपयोग लिये जाने का तथ्य आमजन की शिकायत एवं उपखण्ड अधिकारी की ओर से करवाई गई जांच में प्रमाणित है। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांटकी जानकारी में आने पर अपीलांट स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका में अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित किये हैं। इसके अलावा राजकीय अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा कदीमी रूप से चल रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया गया, जिससे मौके पर कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित खातेदारी भूमि पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिये जाने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं



अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

किया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांत को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदारबायतु द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2016 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदारबायतु को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश बिश्नोई)

अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर

(ए.डी.एम.)

